श्री पी. वी. नरसिंह राव (मरणोपरांत)

श्री पी. वी. नरसिंह राव, भारत के नौवें प्रधान मंत्री थे। वह राष्ट्रवादी, बहुभाषाविद, विद्वान और एक दूरदर्शी राजनेता थे।

2. श्री नरसिंह राव का जन्म 28 जून, 1921 को तेलंगाना के लक्नेपल्ली गांव में हुआ था। उनका जीवन दृढ़ता और सुधार का जीता–जागता उदाहरण था। बचपन में गरीबी, अज्ञानता और मानवाधिकार उल्लंघन ने उनके मन पर गहरा असर डाला। उन्होंने समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने पहले अपने गाँव में अमानवीय व्य वहार के विरुद्ध आवाज उठाई और, जैसे–जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने निजाम के कुशासन और रजाकारों के अत्याचारों का विरोध किया। उन्होंने निजाम की रियासत में मैट्रिक की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, किंतु 'वंदेमातरम' गाकर उन्होंने निजाम के आदेश का उल्लंघन किया और फलस्वरूप उन्हें इंटरमीडिएट से निष्कासित कर दिया गया। इससे विचलित हुए बिना, उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय और फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में अध्ययन किया और गणित एवं खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। इन प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अकादमिक उपलब्धियां प्राप्त की और वह पूरे देश में व्याप्त उग्र ब्रिटिश विरोधी भावना से भी अछूते नहीं रहे। नागपुर वापस आकर उन्होंने विधि स्नातक (एलएलबी) किया और उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

3. स्वतंत्रता के हिमायती राष्ट्रीय नेताओं की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए, श्री नरसिंह राव की शैक्षणिक उपलब्धियों से उनकी विद्रोही भावना प्रबल हुई। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का उनका अनुभव हैदराबाद राज्य में दमनकारी शासन के विरुद्ध उनकी सक्रियता का आधार बना। उनकी विद्वता इस अन्याय का विरोध करने और सुधार के लिए समर्थन प्राप्त करने में सहायक बनी। हैदराबाद लौटने पर, उन्होंने विधि पेशेवर के रूप में करियर शुरू किया, किंतु उनका मन स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में चल रहे निजाम विरोधी आंदोलन में ही लगा रहा। नरसिंह राव की राजनीतिक विचारधारा पर स्वामी जी का बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें सुधारों के प्रति उत्साह का संचार हुआ। यही उत्साह बाद के वर्षों में राज्य सरकार में मंत्री और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों में दिखाई देता है।

4. संयुक्त आंध्र प्रदेश में मंत्री (1962–71) के रूप में, श्री नरसिंह राव ने कारागार सुधार से लेकर तेलुगू को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने जैसी कई परिवर्तनकारी पहल की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (1971–73) के रूप में, उन्होंने साहसिक और अग्रगामी भूमि सुधार किए।

5. मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद, श्री नरसिंह राव ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वह 1975 से 1976 तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। बाद के वर्षों में, उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री, गृह, रक्षा और मानव संसाधन विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन किया। इन सभी पदों पर, उनकी नवीन सोच ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी।

6. जब श्री नरसिंह राव 1991 में राजनीति छोड़ने का विचार कर रहे थे, तब श्री राजीव गांधी की दुःखद हत्या के कारण उन्हें प्रधान मंत्री का पद संभालना पड़ा। प्रधान मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल पंजाब और असम में कानून–व्यवस्था की समस्याओं तथा गंभीर भुगतान संतुलन के संकट के साथ शुरू हुआ। इन समस्याओं को हल करने और उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण द्वारा दूरगामी आर्थिक सुधार शुरु करने का श्रेय उनके नेतृत्व को दिया गया था। उनके नेतृत्व में, भारत ने न केवल मिसाइल, परमाणु और मोबाइल प्रौद्योगिकियों में उल्लेखनीय प्रगति की, बल्कि उनके कार्यकाल में ही मध्याह्न भोजन योजना, पीएम रोजगार योजना आदि जैसे कई कल्याणकारी कार्यक्रम भी शुरू हुए। श्री नरसिंह राव की विरासत, नवोदय स्कूल, लुक ईस्ट पॉलिसी, आर्थिक सुधार और भूमि सुधार जैसी ऐतिहासिक पहलों के साथ भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई है।

7. श्री नरसिंह राव को साहित्य और शिक्षा से बड़ा लगाव था। उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विश्वनाथ सत्यनारायण के 'वेयिपदगलू' का हिंदी में 'सहस्रफन' और हरि नारायण आप्टे के मराठी उपन्यास 'पन लक्षत कोन घेटो' का तेलुगू में 'अबलाजीवितम' के रूप में अनुवाद भी किया। उन्होंने एक अर्ध–कथात्मक आत्मकथा 'इन्साइडर' सहित कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं।

8. श्री नरसिंह राव का 23 दिसंबर, 2004 को निधन हो गया। वह दृढ़ता, सुधार, एक नए और जीवंत भारत के विजन वाली विरासत सौंपकर गए हैं।

Shri P. V. Narasimha Rao (Posthumous)

Shri P.V. Narasimha Rao, the ninth Prime Minister of India, was a nationalist, a polyglot, a man of letters and a visionary statesman.

2. Born on June 28, 1921 at Laknepalli village of Telangana, Shri Narasimha Rao's life was a testament to resilience and reform. He was profoundly moved by the poverty, ignorance and human rights violations he had observed in his childhood. He recognized the need for a shift in societal mindset, rebelling first against inhumane practices he had witnessed in his own village and, as he grew older, against the misrule of the Nizam and the atrocities of the Razakars. While he topped the matriculation examinations in the Nizam dominion, he faced expulsion from the intermediate course for defying the Nizam orders against reciting 'Vandemataram'. Undeterred, he pursued his studies at Nagpur University and Ferguson College, Pune, excelling in Mathematics and Astronomy. These formative years not only honed his academic prowess but also exposed him to the fervent anti-British sentiment sweeping the nation. He returned to Nagpur, pursued his Degree in Law (LLB) and topped as a gold medallist.

3. Shri Narasimha Rao's academic pursuits were imbued with a spirit of rebellion, as he absorbed the teachings of national leaders advocating for independence. His exposure to the anti-British movement laid the foundation for his activism against the oppressive regime in Hyderabad state. His literary endeavours served as a weapon to denounce these injustices and galvanize support for change. On his return to Hyderabad, he embarked on a legal career while his heart remained with the anti-Nizam movement led by Swami Ramananda Tirtha. Swamiji's influence moulded Narasimha Rao's political ideology, imbuing him with a reformatory zeal, which was evident in the reforms he embarked upon in subsequent years as a Minister in the State government and the various positions he held in Central Government.

4. As a minister in the combined Andhra Pradesh (1962-71), Shri Narasimha Rao spearheaded transformative initiatives, from prison reforms to the promotion of Telugu as the official language. The land reforms he had introduced as the Chief Minister of Andhra Pradesh (1971-73) were courageous and path breaking.

5. Following his tenure as the Chief Minister, Shri Narasimha Rao expanded his purview to National politics. He was the General Secretary of the Congress Party from 1975 to 1976. In the subsequent years, he shouldered greater responsibilities as Union Minister of External Affairs, Home, Defence and Human Resource Development. In all these positions, his novel thinking left an indelible mark on the country's political landscape.

6. While Shri Narasimha Rao was planning to retire from politics in 1991, the tragic assassination of Shri Rajiv Gandhi catapulted him to the position of the Prime Minister. His term as the Prime Minister began not only with law-and-order problems in Punjab and Assam, but also with an acute Balance of Payments crisis. His leadership was credited with solving these problems and ushering in far-reaching economic reforms marked by Liberalization, Privatization, and Globalization. Under his stewardship, India witnessed not only remarkable advancements in Missile, Nuclear and Mobile technologies but also several welfare programs like the Mid-Day Meal scheme, PM Rozgar Yojna and so on. Shri Narasimha Rao's legacy is etched in the annals of Indian history through landmark initiatives such as Navodaya schools, Look East Policy, Economic Reforms and Land Reforms.

7. Shri Narasimha Rao was also greatly committed to literature and learning. A prolific writer of short stories, he also translated Jnanpith Awardee Vishwanatha Satyanarayana's 'Veyipadagalu' into Hindi as 'Sahasraphan' and Hari Narayan Apte's Marathi novel 'Pan Lakshat Kon Gheto' into Telugu as 'Abalajeevitham'. He also authored several other books including 'Insider', a semi-fictionalised autobiography.

8. Shri Narasimha Rao passed away on December 23, 2004, leaving behind a legacy of resilience, reform, a vision for a new and vibrant India.

चौधरी चरण सिंह (मरणोपरांत)

चौधरी चरण सिंह एक बहुआयामी व्यक्तित्व और कट्टर देशभक्त, सुयोग्य प्रशासक, कुशल राजनेता और सबसे बढ़कर, चरित्रवान, निष्ठावान तथा मानवतावादी थे।

2. 23 दिसंबर 1902 को संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव के एक किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह की प्राथमिक शिक्षा नजदीकी गांव जानी खुर्द के एक विद्यालय में हुई और उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई मेरठ से की। उन्होंने 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान में स्नातक और इसके बाद, स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1926 में मेरठ कॉलेज, मेरठ से कानून की डिग्री प्राप्त की।

3. चौधरी चरण सिंह 1929 से 1939 तक गाजियाबाद टाउन कांग्रेस कमेटी के संस्थापक सदस्य थे। वह 1939 में मेरठ चले गए और 1939 से 1946 तक उन्होंने मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, महासचिव और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह महात्मा गांधी और महर्षि दयानंद की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के आह्वान पर, वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और तीन बार 1930, 1940 और 1942 में जेल गए।

4. चौधरी चरण सिंह 1937 में पहली बार संयुक्त प्रांत की विधान सभा के लिए मेरठ जिले के गाजियाबाद– बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वह 1977 तक विधायक रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1951 और 1967 के बीच, एक छोटी अवधि को छोड़कर, उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हुए राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया।

5. 1967 के आम चुनाव के बाद, चौधरी चरण सिंह ने अपने 16 समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और जन कांग्रेस नामक एक नए दल की स्थापना की। बाद में पूरा विपक्ष एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) बना। एसवीडी के नेता के रूप में, चौधरी चरण सिंह को 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया बया। आंतरिक तनाव और कलह के कारण एसवीडी सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। विधानसभा में बाद के घटनाक्रम के दौरान, फरवरी 1970 में वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बने।

6. चौधरी चरण सिंह 1977 में पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोक सभा के लिए चुने गए और मोरारजी देसाई सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने श्री राजनारायण को सरकार से हटाने के विरोध में गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उनके बिना सरकार चलाना मुश्किल हो गया । उन्हें फिर से देसाई सरकार में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें वित्त विभाग के साथ उप प्रधान मंत्री बनाया गया।

7. जनता पार्टी में नये घटनाक्रम के फलस्वरूप, श्री मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई, 1979 को प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कई दौर के विचार–विमर्श के बाद, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 28 जुलाई, 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

8. चौधरी चरण सिंह भारतीय अर्थशास्त्र और नियोजन के महान विद्वान थे। उनकी पुस्तकें 'भारत की आर्थिक नीति – गांधीवादी ब्लूप्रिंट' और 'भारत का आर्थिक दुःस्वप्न – कारण और उपाय' भारतीय कृषि विषय पर उत्कृष्ट कृतियां हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तुकों में 'जमींदारी उन्मूलन', 'कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स–रेड', 'भारत की गरीबी और उसके समाधान', 'उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति' और 'यूपी और कुलकों में भूमि सुधार' शामिल हैं। 1942 में उन्होंने बरेली सेंट्रल जेल में भारतीय शिष्टाचार पर एक अनूठी पुस्तक लिखी। यह पुस्तक बाद में 'शिष्टाचार' शीर्षक से प्रकाशित हुई।

9. चौधरी चरण सिंह का 29 मई 1987 को निधन हो गया। किसान समुदाय की बेहतरी के उनके प्रयासों के कारण नई दिल्ली में उनकी समाधि का नाम 'किसान घाट' रखा गया।

Chaudhary Charan Singh (Posthumous)

Chaudhary Charan Singh was a multi-faceted personality and an ardent patriot, an able administrator, an astute statesman and above all, a man of character, integrity and humanist inclinations.

2. Born on 23 December 1902 in a peasant family at Noorpur Village in Meerut District of United Province (Uttar Pradesh), Chaudhary Charan Singh had his primary education in the nearby village school at Jani Khurd and matriculation from Meerut. He graduated in Science in 1923 and secured his Master's degree from Agra College, Agra. He qualified for law degree in 1926 from Meerut College, Meerut.

3. Chaudhary Charan Singh was a founder member of the Ghaziabad Town Congress Committee from 1929 to 1939. He shifted to Meerut in 1939 and served as Treasurer, General Secretary and President of the Meerut District Congress Committee from 1939 to 1946. He was greatly influenced by the teachings of Mahatma Gandhi and Maharishi Daya Nand. At the call of Mahatma Gandhi, he joined the freedom struggle and was sentenced to jail three times - in 1930, 1940 and 1942 respectively.

4. Chaudhary Charan Singh was elected for the first time to the Legislative Assembly of the United Province from Ghaziabad-Baghpat constituency in Meerut District in 1937. He continued to be a legislator till 1977. He played a pivotal role in the eradication of the Zamindari System in Uttar Pradesh. Between 1951 and 1967, except for a short period, he functioned as a member of the State Council of Ministers holding important portfolios.

5. After the 1967 general elections, Chaudhary Charan Singh accompanied by 16 of his followers, quit the Congress and set up a group called the Jan Congress. Later, the entire opposition came together to form the Samyukta Vidhayak Dal (SVD). As a leader of SVD, Chaudhary Charan Singh was appointed as the Chief Minister of Uttar Pradesh on 3rd April 1967. Inner strains and squabbles led to the downfall of the SVD Government and the State was placed under President's rule. In the course of subsequent turn of events in the Assembly, he once again became the Chief Minister in February 1970.

6. Chaudhary Charan Singh was elected to the Lok Sabha for the first time in 1977 as Janata Party candidate and was appointed as Home Minister in Shri Morarji Desai Government. He resigned from Home Ministership in protest against the removal of Shri Raj Narain from the Government. However, without him, the Government found it difficult to function. He was again inducted into the Desai Government and he was appointed Deputy Prime Minister with Finance as his portfolio.

7. Due to new developments in Janata Party, Shri Morarji Desai resigned from the Prime Minister's post on 15th July, 1979. After a series of consultations, the then President, Dr. Neelam Sanjiva Reddy invited Chaudhary Charan Singh to form the government. He was sworn in as the Prime Minister on 28th July, 1979.

8. Chaudhary Charan Singh was a great scholar of Indian economics and planning. His books 'India's Economic Policy - the Gandhian Blueprint' and 'Economic Nightmare of India - Its Cause and cure' are masterpieces on the Indian agrarian theme. Some of his important publications include : 'Abolition of Zamindari', 'Co-operative Farming X-rayed', 'India's Poverty and its Solutions', 'Agrarian Revolution in Uttar Pradesh' and 'Land Reforms in UP and the Kulaks'. In 1942, he wrote an unique book on Indian etiquette in Barreilly Central Jail. This book was published later with the title 'Shishtachar'.

9. Chaudhary Charan Singh passed away on 29th May 1987. His quest for the betterment of the farming community caused his memorial in New Delhi to be named as 'Kisan Ghat'.

डॉ. मणकोम्बू साम्बशिवन स्वामीनाथन (मरणोपरांत)

डॉ. मणकोम्बू साम्बशिवन स्वामीनाथन एक पादप वैज्ञानिक, आनुवंशिकीविद्, प्रशासक, संस्थान–निर्माता और भारत की हरित क्रांति के जनक थे। उन्होंने दुनिया के गरीब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रयोग किया और सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के प्रति पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

2. 7 अगस्त, 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे डॉ. स्वामीनाथन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर से स्नातक की डिग्री और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से साइटोजेनेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। वैगनिंगेन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में यूनेस्को फेलोशिप के बाद, वह जेनेटिक्स में पीएचडी करने के लिए यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

3. केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, डॉ. स्वामीनाथन ने 1954 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में कार्यभार संभाला और इसके निदेशक बने। इसके बाद, उन्होंने महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव; प्रधान सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय; कार्यवाहक उपाध्यक्ष और सदस्य, योजना आयोग; और महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस के रूप में कार्य किया। 1987 में, उन्होंने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और इसके संस्थापक निदेशक और अध्यक्ष बने। वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा पगवाश कांफ्रेंस ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स सहित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भारत सरकार के राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष (2004–06) और संसद सदस्य (राज्य सभा) (2007–2013) के रूप में भी कार्य किया।

4. डॉ. स्वामीनाथन ने आईएआरआई में बेसिक और एप्लायड साइंस में उत्कृष्ट शोध किया। आईएआरआई में अपने शुरुआती करियर के दौरान, उन्होंने गेहूं, अलसी, मिर्च, तम्बाकू, बाजरा, मक्का और चारा फसलों की ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में बहुमूल्य योगदान दिया, और प्रमुख पत्रिकाओं में उनके उल्लेखनीय शोध पत्र प्रकाशित हुए। 1950 और 1960 के दशक के दौरान साइटोजेनेटिक्स, रेडिएशन बायोलॉजी, रेडिएशन और कैमिकल म्यूटाजेनेसिस तथा सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में मौलिक शोध में उनके अग्रणी योगदान के लिए, उन्हें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और रॉयल सोसाइटी, लंदन की फेलोशिप (FRS 1973) प्राप्त हुई।

5. डॉ. स्वामीनाथन की अगुआई में अधिक उपज वाली गेहूं की कम ऊंचाई वाली किस्मों और बासमती स्ट्रेन के विकास के लिए शोध किया गया, जिसने फसल पैदावार की भरपूर वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाते हुए भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। इसी वजह से उन्हें 'भारत की हरित क्रांति के जनक' की उपाधि मिली।

6. डॉ. स्वामीनाथन का सरोकार बाद में सतत कृषि और खाद्य प्रणालियों, या जिसे उन्होंने "सदाबहार क्रांति" कहा, की ओर मुड़ गया जिससे लगातार कृषि की अधिक उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर अग्रणी शोध किया और जलवायु परिवर्तन को सतत कृषि का मुख्य विषय बनाया। उन्होंने आनुवंशिक संसाधनों के संग्रह और संरक्षण के वैश्विक महत्व को पहचाना और भारत तथा अन्य स्थानों पर जीनबैंक में महत्वपूर्ण संग्रह तैयार करने में मदद की। वह कृषि जैव विविधता के सतत उपयोग के बारे में भी चिंतित थे, और उन्होंने भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा विधान बनाने में योगदान दिया जिससे किसानों और देशी समुदायों के साथ लाभ साझा किए जा सके।

7. डॉ. स्वामीनाथन भारत में आधुनिक कृषि अनुसंधान और शिक्षा के प्रवर्तक थे और उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की रूपरेखा बनाने, कृषि अनुसंधान सेवा की स्थापना और कृषि विज्ञान केन्द्रों के संगठन के माध्यम से किसानों का प्रशिक्षण जैसे कई उपायों से अपनी छाप छोड़ी।

8. डॉ. स्वामीनाथन का हर प्रयास पुरुष और महिला किसानों के लिए लाभकारी नीतियों को बढ़ावा देना था। उन्होंने "लैब टू लैंड" कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों को किसानों के खेतों तक पहुंचाना और कृषि अनुसंधान व नीति में जेंडर संबंधी सरोकारों को एक साथ लाना था। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, कृषि के रूप में, उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार जेंडर और पर्यावरण दृष्टिकोणों को शामिल किया।

9. डॉ. स्वामीनाथन एक अंतरराष्ट्रीयवादी थे और उन्होंने अन्य विकासशील देशों में कृषि अनुसंधान केंद्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईआरआरआई के पहले एशियाई महानिदेशक के रूप में, उन्होंने चावल की खेती करने में लगी महिलाओं की ओर ध्यान दिलाया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत बनाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और कृषि संगठन तथा अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों का नेतृत्व करते हुए, दुनिया में भूख और गरीबी को खत्म करने की कार्यनीतियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

10. डॉ. मणकोम्बू साम्बशिवन स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया।

Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan (Posthumous)

Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan was a plant scientist, geneticist, administrator, institution-builder, and the father of India's green revolution. He dedicated his entire life to ensuring food and nutrition security for all, using his scientific talent to address the problems of the world's poor.

2. Born on August 7, 1925, in Kumbakonam, Tamil Nadu, Dr. Swaminathan completed undergraduate degrees from University College, Thiruvananthapuram and Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, and a Master's in Cytogenetics from the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. Following a UNESCO Fellowship at Wageningen Agricultural University, he went to the University of Cambridge, UK to pursue his PhD in Genetics.

3. After a brief spell at the Central Rice Research Institute, Cuttack, Dr. Swaminathan joined the Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi in 1954 and rose to become its Director. Thereafter, he served as Director General, Indian Council of Agricultural Research and Secretary to the Government of India, Department of Agricultural Research and Education; Principal Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture; Acting Deputy Chairman and Member, Planning Commission; and Director General, International Rice Research Institute, Philippines. In 1987, he founded the M S Swaminathan Research Foundation and was its founding Director and Chairman. He was President of several important international organisations including the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources and Pugwash Conferences on Science and World Affairs. He also worked as Chairman, National Commission on Farmers, Government of India (2004-06) and Member of Parliament (Rajya Sabha) (2007-2013).

4. Dr. Swaminathan conducted outstanding research in basic and applied science at IARI. During his early career at the IARI, he made valuable contributions to the breeding and genetics of wheat, linseed, chilli, tobacco, bajra, maize, and forage crops, generating outstanding publications in major journals. For his path-breaking contributions to basic research in cytogenetics, radiation biology, radiation and chemical mutagenesis, and cell biology during the 1950s and 1960s, he received the Shanti Swarup Bhatnagar Award in 1961 and Fellowship of the Royal Society, London (FRS 1973).

5. Dr. Swaminathan led research to develop high-yielding dwarf wheat varieties and basmati strains which played a pivotal role in the remarkable increase in crop yields that steered India towards self-sufficiency in food production. This earned him the title of the 'Father of India's Green Revolution.'

6. Dr. Swaminathan's concern later turned to sustainable agriculture and food systems, or what he termed "evergreen revolution" to ensure higher agricultural productivity in perpetuity. He pioneered research on global warming and made climate change a central concern of sustainable agriculture. He recognised the global importance of collection and conservation of genetic resources and helped build critical collections in genebanks in India and elsewhere. He was equally concerned with sustainable use of agrobiodiversity, and contributed to legislation in India and internationally that assured benefit-sharing with farmers and indigenous communities.

7. Dr. Swaminathan was the principal architect of modern agricultural research and education in India and made an impact in numerous ways from shaping higher education in Agricultural Universities, setting up the Agricultural Research Service, and implementing farmers' training via the organisation of Krishi Vigyan Kendras.

8. Dr. Swaminathan's every effort was to promote policies beneficial to men and women farmers. He initiated "Lab to Land" programme that aimed to transfer new technologies to farmers' fields and integrate gender concerns in agricultural research and policy. He recommended for Minimum Support Price as Chairman of the National Farmers' Commission. As vice-chair and Member, Agriculture of the Planning Commission, he included gender and environmental perspectives for the first time in the Sixth Five Year Plan.

9. Dr. Swaminathan was an internationalist and was instrumental in the creation of centres of agricultural research in other developing countries. As the first Asian Director-General of IRRI, he brought attention to women in rice farming and strengthened agricultural research systems across South East Asia. Leading important bodies of the United Nations, the Food and Agriculture Organisation and the Consultative Group on International Agriculture Research, among others, he played a definitive role in developing strategies to end global hunger and poverty.

10. Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan passed away on 28th September, 2023.

श्री कर्पूरी ठाकुर (मरणोपरांत)

श्री कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनेता तथा किसानों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के हितैषी थे। जनहित के कार्यों के कारण जनमानस उन्हें 'जननायक' कह कर पुकारती है। उनका जीवन लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के अथक प्रयास की मिसाल है।

2. श्री ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के दरभंगा (समस्तीपुर) जिले के पीतौंझिया (अब कर्पूरी ग्राम) में विदेशी शासन वाले भारत के जातिग्रस्त समाज में एक सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ। श्री ठाकुर ने स्कूल जाने का संकल्प किया। वह जमींदारों की विशाल हवेलियों के बाहर तपती धूप में खड़े रहते और उन्होंने हवेली के अंदर सुविधाप्राप्त बच्चों को पढ़ाए जा रहे पाठों को सुनकर पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किया। वह उस समय दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुछ लोगों में से थे। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए, उन्होंने प्रतिष्ठित सीएम कॉलेज में दाखिला पाया। इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई जारी रखी।

3. श्री ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर 14 वर्ष की अल्पायु में नवयुवक संघ का गठन किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कृषक आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने 1945 में जेल से रिहा होने के बाद भी ब्रिटिश राज के विरुद्ध और भूमिहीन किसानों के हित में अहिंसक संघर्ष जारी रखा। वह 1948 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रांतीय मंत्री चुने गए और हिंद किसान पंचायत की केंद्रीय समिति के सदस्य भी बने। वह 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में विजयी हुए। 1957 और 1962 के चुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बिहार विधानसभा में भूमिहीन किसानों की दुर्दशा के विरुद्ध आवाज उठाई और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों पर लगातार हो रहे जाति–आधारित उत्पीड़न की निंदा की। वह 1967 में बिहार के उप–मुख्यमंत्री बने और शिक्षा एवं वित्त मंत्रालयों का प्रभार संभाला। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क कर दिया तथा शिक्षा को समावेशी और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। उन्होंने 7 एकड़ तक की भूमि जोत पर भू–राजस्व से छूट प्रदान की।

4. श्री ठाकुर ने 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदग्रहण करने के बाद, सरकार को जनता तक पहुंचाने और बेहतर जन कल्याण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किया। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाया और वृद्धावस्था पेंशन शुरू की। पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, उन्होंने इंजीनियरों और डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया, और उनके नियुक्ति–पत्र सार्वजनिक मंच से वितरित किए। उनके द्वारा किए गए भूमि सुधारों से सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। उन्होंने छोटे किसानों का भू–राजस्व बकाया माफ कर दिया और भूमि पर अधिभार को समाप्त किया।

5. श्री ठाकुर विधान सभा के सभी चुनाव जीतते रहे। हालांकि, उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नाम से लोकप्रिय जन आंदोलन जेपी आंदोलन में भाग लेने के लिए 1974 में विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1975–77 के आपातकाल के दौरान भी अज्ञात स्थानों से नेतृत्व करके इस जन आंदोलन को जीवित रखा। वह 30 जनवरी 1977 को पटना के गांधी मैदान में विशाल जन सभा के समक्ष मंच पर उपस्थित हुए और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। सभी लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने के लिए किए गए निरंतर निडर और निस्वार्थ जन आंदोलन के बाद आपातकाल को वापस लिया गया और चुनाव कराए गए।

6. श्री ठाकुर के नेतृत्व में, चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद वह 24 जून 1977 को फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गरीबी–निरक्षरता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए दसवीं कक्षा तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया। उन्होंने आबादी के एक बड़े हिस्से की भाषा उर्दू को भी दूसरी राजभाषा बनाया। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए पहली बार अंत्योदय योजना लागू की। उन्होंने पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों, महिलाओं और उच्च जातियों के गरीबों के लिए शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी लागू किया।

7. हालांकि, श्री ठाकुर को सामंतवादी प्रणाली के विशेषाधिकार और सुविधाप्राप्त लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु वह सामाजिक न्याय के पथ पर डटे रहे। उनका जीवन ऐसे समाज को विकास पथ पर आगे बढ़ाने की संघर्ष गाथा है, जहां सभी को अपनी क्षमता साकार करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का समान अवसर मिले।

8. श्री कर्पूरी ठाकुर का 17 फरवरी, 1988 को निधन हो गया।

Shri Karpoori Thakur (Posthumous)

Shri Karpoori Thakur was a freedom fighter, a visionary statesman and a champion of the cause of farmers, women and disadvantaged sections of society. People call him 'Jannayak' for his work for the cause of common people. His life is a testament to the relentless pursuit of deepening democracy, embodying the principles of liberty, equality and fraternity enshrined in the Constitution of India.

2. Born on 24 January 1924 at Pitaunjhia (now Karpoori Gram) in Darbhanga (Samastipur) district of Bihar in a socially, educationally and politically disadvantaged family in a caste-ridden society of foreign-ruled India. Shri Thakur insisted on attending school. He acquired knowledge from textbooks by listening to lessons meant for the privileged children of Zamindars, all the while perched at the footsteps outside the grand expanse of their Haveli. He was among a few at that time who passed Class 10th Board examination. Undeterred by the social and economic challenges, he enrolled in the prestigious CM College. After completing intermediate, he continued his studies for graduation.

3. Shri Thakur, inspired by the freedom struggle, formed the Navyuvak Sangh at the age of 14 and took part in the farmers' movement led by Swami Sahajanand Saraswati. He actively participated in the Quit India Movement and was arrested in 1943. He continued a non-violent struggle against the British Raj and for the landless farmers even after his release from jail in 1945. He was elected provincial minister of the Socialist Party, formed under the leadership of Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan in 1948, and also became a member of the Central Committee of Hind Kisan Panchayat. He won the first election of Independent India in 1952 as a Socialist Party nominee. Continuing to represent Tajpur in the assembly after winning the 1957 and 1962 elections, he raised his voice against the plight of the landless peasants and denounced the continuing caste-based oppression of scheduled castes, scheduled tribes and backward castes in the Bihar assembly. He became the Deputy Chief Minister of Bihar in 1967 holding the Education and Finance Ministries. He made primary education free to help the poor and removed the mandatory requirement of passing English to pass the 10th Examination to make education inclusive and more relevant. He exempted land rent on land holdings up to 7 acres.

4. Assuming office as the Chief Minister of Bihar on 22nd December 1970, Shri Thakur implemented several significant reforms aimed at enhanced accessibility to governance and improving welfare of the populace. He made Hindi as the language of the government and instituted old age pension. With an aim to promote transparency, he overhauled the appointment process of engineers and doctors, distributing their appointment letters in public. His commitment to social justice was further evidenced by his initiation of land reforms. He waived the revenue obligations of the small scale farmers and abolished surcharges on land.

5. Shri Thakur continued winning all elections to represent in the Legislative Assembly. However, he resigned as a Member of the Legislative Assembly in 1974 to participate in the mass movement popularly known as the JP movement after the name of Jayaprakash Narayan. He kept the mass movement alive by leading it from undisclosed places, even during the emergency period of 1975-77. He appeared on a public stage on 30 January 1977 and was arrested before a mammoth gathering of people in Patna's Gandhi Maidan. The continued fearless and selfless mass movement to restore all democratic rights later led to the withdrawal of the emergency and the holding of an election.

6. Shri Thakur again became the Chief Minister of Bihar on 24th June 1977, after leading the coalition to victory in the election and made education free till the 10th class to break the vicious cycle of poverty- illiteracy. He also recognized Urdu, a language of a large segment of the population, as the second official language. He implemented the Antyodaya Yojana for the first time to provide free food grains through the public distribution system. He also implemented reservation in educational institutions and government jobs for backward castes, extremely backward castes, women, and poor upper castes.

7. Shri Thakur, however, had to face the opposition from the privileged and beneficiaries of the feudal structure but he remained steadfast in his pursuit of social justice. His life has been a story of the struggle to steer society on the just course of development path where everyone gets an equal opportunity to realize his potential and contribute to nation-building.

8. Shri Karpoori Thakur passed away on 17th February, 1988.